

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 222/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम बनाम 1. सांवरिया लाल पिता नानूराम सुथार निवासी
विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) नई परासौली तहसील आसीन्द
ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति 2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक
आसीन्द जिला भीलवाडा निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत
परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी
जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत
समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला
भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994
बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् पट्टा संख्या 01

प्रकरण संख्या – 223/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम बनाम 1. भंवर लाल पिता मोती लाल जाट निवासी
विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) नई परासौली तहसील आसीन्द
ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति 2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक
आसीन्द जिला भीलवाडा निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत
परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी
जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत
समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला
भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994
बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् पट्टा संख्या 31

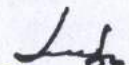
प्रकरण संख्या – 225/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम बनाम 1. लेहरू लाल पिता सुखदेव जाट निवासी नई
विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) परासौली तहसील आसीन्द
ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति 2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक
आसीन्द जिला भीलवाडा निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत
परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी
जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत
समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला
भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994
बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् पट्टा संख्या 44


अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रकरण संख्या – 226/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

- बनाम
1. सांवरिया लाल पिता नानूराम सुथार निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
 2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् पट्टा संख्या 58

प्रकरण संख्या – 229/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

- बनाम
1. भंवर लाल पिता लखमा राम जाट निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
 2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् पट्टा संख्या 63

प्रकरण संख्या – 235/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

- बनाम
1. लक्ष्मण लाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
 2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् पट्टा संख्या 86



[Signature]
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रकरण संख्या – 239/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

- बनाम 1. श्रीमती नन्दूदेवी पत्नी छौगा कुमावत निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् पट्टा संख्या 60

प्रकरण संख्या – 240/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

- बनाम 1. श्रीमती नन्दूदेवी पत्नी छौगा कुमावत निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् पट्टा संख्या 53

प्रकरण संख्या – 241/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

- बनाम 1. सांवरिया लाल पिता भैरूलाल कुमावत निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् पट्टा संख्या 62

Handwritten Signature
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रकरण संख्या – 242/2020 – निगरानी

- ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम बनाम 1. सुवालाल पिता पन्ना लाल जाट निवासी नई विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) परासौली तहसील आसीन्द
- ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा 2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994
बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् पट्टा संख्या 54

उपस्थित (उक्त सभी 10 प्रकरणों में)–

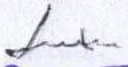
1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीशचन्द्र दाधीच अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.05.2023

निगराकार ने उक्त सभी 10 प्रकरणों में एक समान विषय वस्तु की गैर निगराकारान् के विरुद्ध अलग अलग निगरानीयां पेश की हैं। उक्त सभी निगरानीयां एक ही प्रकृति की होकर अलग अलग पट्टों को निरस्त किये जाने बाबत् निगरानीयां पेश की हैं। समान विषय वस्तु होने से उक्त सभी 10 निगरानी प्रकरणों में एक साथ निर्णय लिखाया जा रहा है।

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान् के प्रस्तुत किया हैं। कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत परासौली के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र मे स्थित भूखण्ड का आवासीय पट्टा पैतृक भूमि मानते हुये जारी किया गया है, जो कि अवैध होकर शून्य प्रभावी है। तथाकथित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोपाल मारू द्वारा ग्राम पंचायत परासौली की कौरम आयोजित नहीं की व प्रस्ताव लिये बिना ही पैतृक भूमि बताकर ग्राम पंचायत में 200/-रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पट्टा जारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पट्टों पर कोई हस्ताक्षर नहीं हैं, हस्ताक्षर किशन नायक के फर्जी किये गये हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा एक आम सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22/11/2020 को प्रकाशन कराई जिसमे सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये ग्राम पंचायत के स्वामित्व मे खाली भूखण्ड है यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पट्टे प्राप्त करता है तो उसकी स्वयं


अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

की जिम्मेदारी है यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पट्टे प्रक्रियात्मक नहीं है। पंचायत समिति में जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पट्टों की प्रतियां पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। जिनकी निगरानिया दर्ज है। तथाकथित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होकर 100 सो फीट रोड़ पर है जो ब्यावर अजमेर मुख्य मार्ग पर स्थित है जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होकर आवासीय व वाणिज्यिक भूमि है जो निलामी के जरिए ही ग्राम पंचायत उक्त भूमि को विक्रय कर सकती है जिससे कि ग्राम पंचायत परासौली को अधिकतम आय प्राप्त हो सके किन्तु ग्राम पंचायत परासौली के पूर्व सरपंच द्वारा पट्टा बहियों को पंचायत व पंचायत समिति से गायब कर पट्टे देकर लोगों से रूपये ँठ लिए, अनपढ ग्रामीण परिवेश के लोगों को फर्जी पट्टे देकर लाखों रूपये हड़प लिए जिसके लिए सरपंच के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक एवं फौजदारी कार्यवाही अलग से अमल में लाई जा रही है अतः तथाकथित पट्टा विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी जो अपास्त होने लायक हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार का निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 का स्वीकार फरमाया जाकर तथाकथित पट्टा दिनांक 05/09/2019 को विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी किया जिसे निरस्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 28.12.2020 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिकार पत्र पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि तथाकथित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोपाल मारू द्वारा ग्राम पंचायत परासौली की कौरम आयोजित नहीं की व प्रस्ताव लिये बिना ही पैतृक भूमि बताकर ग्राम पंचायत में 200/-रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पट्टा जारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पट्टों पर कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा एक आम सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22/11/2020 को प्रकाशन कराई जिसमें सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये ग्राम पंचायत के स्वामित्व में खाली भूखण्ड है यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पट्टे प्राप्त करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पट्टे प्रक्रियात्मक नहीं है। पंचायत समिति में जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पट्टों की प्रतियां पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार का निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 का स्वीकार फरमाया जाकर तथाकथित पट्टा दिनांक 05/09/2019 को विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी किया जिसे निरस्त फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने विधिक प्रक्रिया अपनाकर मजमे आम में प्रश्नगत पट्टा जारी किया हैं। ग्राम



Luks

अति. जिला कलक्टर
भानुवाड़ा

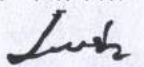
पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157 के तहत प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पट्टाधारी का उस भूखण्ड पर 50 वर्ष या अधिक समय का कब्जा मुख्य आधार माना जाता है। तत्कालीन सचिव द्वारा जारीशुदा पट्टों का पंजीयन कराया गया। पंजीयन दस्तावेजात में तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर किये हुये हैं। जिससे जाहिर होता है कि पट्टे विधि तौर जारी किये गये हैं, उनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। प्रश्नगत पट्टे की फोटोप्रति पेश की जा रही हैं जिसमें तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर हो रखे हैं। ऐसे में यह सिद्ध होता है कि प्रश्नगत पट्टा विधिनुकूल सही तौर जारी किया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही होने से निगराकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 53, 44, 58, 31, 62, 63, 86, 54, 01, 60 दिनांक 05.09.2019 की वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत परासोली द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 53, 44, 58, 31, 62, 63, 86, 54, 01, 60 दिनांक 05.09.2019 की सत्यापित प्रति से परीक्षण करने पर जाहिर होता है कि पट्टा संख्या 53, 62, 86, 54, 01, 60 पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर हैं एवं न ही सचिव के हस्ताक्षर हैं एवं पट्टा संख्या 44, 58, 31, 63 पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर हैं, सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा उक्त सभी पट्टों में किसी पर भी सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रश्नगत पट्टा विधिक रूप से पूर्णतया त्रुटिपूर्ण हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत परासोली श्री किशनलाल नायक ने दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22.11.2020 को आम सूचना प्रकाशित करवायी गयी जिसमें सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये, ग्राम पंचायत के स्वामित्व में खाली भूखण्ड है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पट्टे प्राप्त करता है, तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। यह पट्टे खारिज योग्य होकर उक्त भूमि के पट्टे प्रक्रियात्मक नहीं है। पंचायत समिति में जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पट्टों की प्रतियों पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। जिनकी निगरानिया दर्ज है।

उक्त आम सूचना प्रकाशन के उपरान्त एवं इस न्यायालय द्वारा सम्मन नोटिस तामील होने के पश्चात् भी गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से निगरानी एवं आम सूचना के खण्डन में कोई प्रत्युत्तर एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं हुये। जिससे न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा पूर्णतया कूटरचित एवं फर्जी है।

प्रश्नगत पट्टे के संबंध में तत्कालीन सचिव एवं प्रस्तुत निगरानी में वर्तमान सचिव के जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु दोनों को पट्टे के संबंध में मूल रिकार्ड के साथ तलब किया गया। वर्तमान सचिव द्वारा प्रस्तुत मूल रिकार्ड से पत्रावली पर


अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपलब्ध दस्तावेजात का मिलान किया जाकर गहनता से परीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि पटटे पर तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं मूल पटटा बही में भी द्वितीय व तृतीय परत पर भी तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे स्पष्ट होता है प्रश्नगत पटटे पूर्णतया विधि विपरीत जारी किये गये हैं। वर्तमान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा अपने जवाब में भी उक्त प्रश्नगत पटटे को विधि विरुद्ध मानते हुये खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

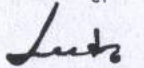
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज परीक्षण में पाया गया कि तहसीलदार आसीन्द के आदेश दिनांक 21.11.2022 के क्रम में पटवार हल्का परासोली का पर्चा मौका दिनांक 22.11.2022 अनुसार – ग्राम परासोली के आराजी नं. 8, 13, 1551 मोके पर खाली होकर अंग्रेजी बबूल खड़े हुये हैं। आराजी नं. 13 में मौके पर नाडी बनी होकर भराव क्षेत्र हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत पटटा विधि विरुद्ध जारी किया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लंघना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरुद्ध तरीके से जो पट्टा संख्या 58 जारी दिनांक 05.09.2019 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता है एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है।

पटटा दिनांक 05.09.2019 को कार्यरत सचिव ग्राम पंचायत परासोली ने खाली भूखण्डों/नाडी भराव क्षेत्र वाली भूमि के पटटे विधि विरुद्ध तरीके से जारी कर, सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद कई पटटो के पंजीयन दस्तावेजात पर स्वयं के हस्ताक्षर किये जाने का कार्य किया है, जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। अतः विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पटटा संख्या 58, 44, 31, 63, 86, 60, 53, 62 के पंजीयन/बिना पंजीयन दस्तावेज की फोटोप्रति से तत्कालिन सचिव के हस्ताक्षर का इस पत्रावली पर उपलब्ध पटटा संख्या 58, 44, 31, 63, 86, 60, 53, 62 पर तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर से मिलान किया जाकर एवं तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर किये जाने व नहीं किये जाने की सत्यता की पूर्ण जांचकर, यदि जांच रिपोर्ट में तत्कालीन सचिव दोषी पाया जाता है तो, तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम पंचायत परासोली के विरुद्ध उक्त प्रश्नगत पटटों के संबंध में विभागीय जांच की जाकर, सी.सी.ए. रूल्स 1958 के तहत कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा को लिखा जाना युक्तियुक्त है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत उक्त 10 निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत उक्त 10 निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 01, 31, 44, 58, 63, 86, 60, 53, 62, 54 किता 10 पटटे, जारी दिनांक 05.09.2019 को निरस्त किया जाता है। पटटा दिनांक 05.09.2019 को कार्यरत सचिव ग्राम पंचायत परासोली ने खाली भूखण्डों/नाडी भराव क्षेत्र वाली भूमि के

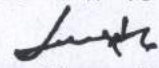

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा



पटटे विधि विरुद्ध तरीके से जारी कर, सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद कई पटटो के पंजीयन दस्तावेजात पर स्वयं के हस्ताक्षर किये जाने का कार्य किया है, जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। अतः विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पटटा संख्या 58, 44, 31, 63, 86, 60, 53, 62 के पंजीयन/बिना पंजीयन दस्तावेज की फोटोप्रति से तत्कालिन सचिव के हस्ताक्षर का इस पत्रावली पर उपलब्ध पटटा संख्या 58, 44, 31, 63, 86, 60, 53, 62 पर तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर से मिलान किया जाकर एवं तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर किये जाने व नही किये जाने की सत्यता की पूर्ण जांचकर, यदि जांच रिपोर्ट में तत्कालीन सचिव दोषी पाया जाता है तो, तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम पंचायत परासोली के विरुद्ध उक्त प्रश्नगत पटटों के संबंध में विभागीय जांच की जाकर, सी.सी.ए. रूल्स 1958 के तहत कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा को लिखा जावे। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा, विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द एवं ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उक्त सभी 10 निगरानी प्रकरणों में अलग अलग संलग्न की जावे।




(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा